3

जनता के बीच सेतु का काम करते हैं कैलाशजी

6

साय के निर्देश पर हॉस्पिटल का उन्नयन

7

सिर्फ एक पर्व नहीं, जीवन बदलने का उत्सव

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 16 | प्रति सोमवार, 25 अगस्त 2025 | मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

देश में उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा, डॉ. जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से गरमाई राजनीति

उपराष्ट्रपति का चुनाव तो हो जायेगा लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगी कालिख कभी नहीं मिटाई जा सकेगी

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब वर्तमान उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल की पूर्णावधि से पहले ही इस्तीफा दे दिया हो। डॉ. जगदीप धनखड़ के अचानक दिए गए इस्तीफे ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और सत्तारूढ़ दल भाजपा के लिए भी यह गहन चिंतन और मनन का विषय बन गया है। इसी के साथ चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख घोषित कर दी है, जिसके बाद एनडीए और यूपीए दोनों ने अपने-अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अब देश की निगाहें इस चुनावी मुकाबले पर टिकी हैं।

इस तरह तैयार हुई इस्तीफे की पृष्ठभूमि

डॉ. जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपने राजनीतिक और कानूनी कौशल से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में पहचान बनाई थी, अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि उनका इस्तीफा निजी कारणों से है, राजनीतिक दबाव का परिणाम है या फिर किसी गहरी असहमति का संकेत है। राजनीतिक सूत्रों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों से धनखड़ और सत्ता पक्ष के बीच संसदीय कार्यप्रणाली और विपक्ष के मुद्दों पर मतभेद बढ़ते जा रहे थे। विपक्ष का कहना है कि धनखड़ कई मौकों पर भाजपा की लाइन से हटकर तटस्थ रुख अपनाते रहे, जिससे पार्टी नेतृत्व असहज महसूस कर रहा था। वहीं भाजपा समर्थक नेताओं का कहना है कि इस्तीफा एक व्यक्तिगत निर्णय है और उसे राजनीति से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। (शेष पेज 2 पर)

मोहन सरकार एक्शन मोड में, भोपाल के ड्रग्स माफिया शारिक मछली पर गिरी गाज

क्या शारिक को संरक्षण देने वाले मंत्री विश्वास सारंग पर कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री यादव?

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति और अपराध के गठजोड़ पर अब बड़ा पर्दाफाश होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में प्रदेश और राजधानी भोपाल के सबसे बड़े ड्रग्स माफिया के रूप में उभरे शारिक मछली पर कड़ा शिकंजा कसा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि शारिक मछली कोई आम अपराधी नहीं बल्कि मध्यप्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का नेता था, जिसने राजनीतिक चोला पहनकर वर्षों तक अपने काले कारनामों को ढकने की कोशिश की। सूत्रों के अनुसार, भोपाल और आसपास के इलाकों में ड्रग्स की सप्लाई, अवैध कारोबार और जमीनों पर कब्जे का जाल शारिक मछली और

उसके परिवार ने वर्षों से फैला रखा था। यह सब संभव हुआ राजनीतिक संरक्षण के कारण। राजनीतिक पहचान और पदवी ने मछली परिवार को न केवल कानून से बचाया बल्कि उनका रसूख इतना बढ़ गया कि वे सत्ता और प्रशासन दोनों के साथ आँख में धूल झोंकते रहे। सवाल यह उठता है कि आखिरकार एक माफिया भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का नेता कैसे बन बैठा? क्या पार्टी को उसकी असलियत का अंदाजा नहीं था, या फिर जानबूझकर आँखें मूँदी गई थीं? (शेष पेज 2 पर)

भूपेश बघेल पर बढ़ा संकटः बेटे की गिरफ्तारी के बाद मानसिक संतुलन खोने के संकेत, खुद कर बैठे खुलासा

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों न सिर्फ राजनीतिक रूप से घिरे हुए हैं, बल्कि निजी मोर्चे पर भी बड़ा संकट झेल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद घटनाक्रम जिस तेजी से बदला है, उसने राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों के अनुसार, ईडी की पूछताछ में चैतन्य बघेल ने कई ऐसे राज उजागर किए हैं जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की ओर इशारा करते हैं। वहीं, इन खुलासों के बाद अब भूपेश बघेल स्वयं भी जांच एजेंसियों के निशाने पर आ चुके हैं और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ देखा जाये तो प्रदेश कांग्रेस नेताओं को बघेल के बेटे के बचाव में आने से बचना चाहिए। (शेष पेज 3 पर)

ईडी के सामने चैतन्य बघेल ने खोले कई राज, 'चंडाल चौकड़ी' के कारनामों से उठ सकता है पर्दा

उपराष्ट्रपति का चुनाव तो हो जायेगा लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगी कालिख कभी नहीं मिटाई जा सकेगी

(पेज 1 का शेष)

पहली बार घटित हुई ऐतिहासिक घटना

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इससे पहले किसी उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा नहीं दिया था। यह पहला अवसर है जब संवैधानिक परंपरा और राजनीतिक परिदृश्य दोनों को एक झटका लगा है। इससे साफ जाहिर होता है कि देश की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहाँ संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति भी असहमति जताने से पीछे नहीं हट रहे।

भाजपा और एनडीए के लिए चिंता

भाजपा के लिए यह इस्तीफा एक बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति हमेशा से यह रही है कि संवैधानिक पदों पर पार्टी के भरोसेमंद और अनुशासित नेताओं को जगह दी जाए। लेकिन धनखड़ के इस्तीफे ने इस रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा की चिंता यह भी है कि विपक्ष इस घटना को "लोकतांत्रिक असंतोष" के रूप में पेश कर सकता है और आने वाले चुनावों में इसे जनता के बीच भुना सकता है। वहीं एनडीए को अब नया चेहरा तलाशने की चुनौती है, जो न केवल उपराष्ट्रपति पद की गरिमा निभा सके बल्कि राजनीतिक समीकरणों में भी संतुलन बैठा सके।

धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष की प्रतिक्रिया

यूपीए और विपक्षी गठबंधन ने धनखड़ के इस्तीफे को भाजपा की नीतियों और लोकतंत्र पर संकट का प्रतीक बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह इस्तीफा दर्शाता है कि भाजपा अपने ही नेताओं को स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं देती। वहीं वामदलों और क्षेत्रीय दलों ने भी इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हो रहे दबाव का उदाहरण बताया। विपक्ष अब इस मुद्दे को संसद और सड़कों दोनों पर उठाने की तैयारी में है। इससे भाजपा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

एनडीए और यूपीए के प्रत्याशी मैदान में

चुनाव आयोग की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों ने तेजी से अपने प्रत्याशी तय किए। एनडीए की ओर से इस बार एक वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को चुना है। पार्टी का मानना है कि इससे भाजपा की समावेशी राजनीति की छवि और मजबूत होगी। यूपीए ने एक प्रखर संवैधानिक वकील और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है, जिनका झुकाव लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा करने की ओर माना जाता है। यह मुकाबला अब केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष माना जा रहा है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल

धनखड़ का इस्तीफा उस समय आया है जब देश में संसद की कार्यप्रणाली पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार कहता आया है कि संसद में उनकी आवाज दबाई जाती है और संसदीय परंपराओं का पालन नहीं हो रहा। उपराष्ट्रपति का पद मूलतः तटस्थ और संतुलित होना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ भी दबाव और असहमति की स्थिति बनती है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएँ सचमुच स्वतंत्र रूप से काम कर पा रही हैं या वे सत्ताधारी दल के प्रभाव में झुक रही हैं। आम जनता के लिए उपराष्ट्रपति का पद भले ही सीधे जीवन से जुड़ा न लगे, लेकिन ऐसी घटनाएँ नागरिकों के भरोसे को प्रभावित करती हैं। लोग यह सवाल उठाने लगे हैं कि यदि देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा, तो फिर लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है, जहाँ लोग इस्तीफे को लोकतंत्र की चेतावनी बता रहे हैं।

आने वाले चुनाव पर होगा असर

इस इस्तीफे और उपराष्ट्रपति चुनाव का असर केवल संसद भवन तक सीमित नहीं रहेगा। भाजपा के लिए यह अग्निपरीक्षा होगी कि वह अपने उम्मीदवार को जिताने के साथ-साथ पार्टी की छवि को भी बचा पाए। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसे वह आगामी लोकसभा चुनावों तक उछाल सकता है। वहीं क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी निर्णायक होगी क्योंकि वे दोनों खेमों के लिए समर्थन जुटाने में अहम साबित हो सकते हैं। डॉ. जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारतीय लोकतंत्र के लिए एक असामान्य और ऐतिहासिक घटना है। यह न केवल संवैधानिक परंपरा पर सवाल खड़े करता है, बल्कि राजनीतिक दलों की कार्यशैली को भी कठघरे में खड़ा करता है। भाजपा और एनडीए के लिए यह आत्ममंथन का समय है कि आखिर किन परिस्थितियों ने उपराष्ट्रपति को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया। वहीं विपक्ष इसे जनता के बीच लोकतांत्रिक असंतोष के प्रतीक के रूप में भुनाने की पूरी कोशिश करेगा।

मोहन सरकार एक्शन मोड में, भोपाल के ड्रग्स माफिया शारिक मछली पर गिरी गाज

(पेज 1 का शेष)

संरक्षण की राजनीति, विश्वास सारंग का नाम

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यह है कि आखिर मछली परिवार को इतना संरक्षण किसने दिया? सूत्रों के अनुसार, नरेला विधानसभा से विधायक और भाजपा नेता विश्वास सारंग ने लंबे समय तक मछली परिवार को राजनीतिक छत्रछाया प्रदान की। यही वजह रही कि प्रशासन के अधिकारी भी वर्षों तक इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराते रहे। सारंग पर आरोप है कि उन्होंने न केवल मछली परिवार के प्रभाव को नजरअंदाज किया बल्कि कई मौकों पर उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन भी किया। विपक्ष ने इस मुद्दे को पकड़कर भाजपा सरकार पर करारा हमला शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ड्रग्स और अपराध के खिलाफ चाहे जितना शोर मचाए, लेकिन सच्चाई यही है कि उसके ही नेता माफियाओं को संरक्षण देते रहे हैं।

करोड़ों की संपत्तियों पर कब्जा

शासन और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में खुलासा हुआ है कि मछली परिवार ने अपने राजनीतिक रसूख का उपयोग करते हुए भोपाल और आसपास करोड़ों रुपये की सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध कब्जा किया। कई व्यावसायिक भूखंड और मकान फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर हथिया लिए गए। गरीबों और मध्यम वर्ग के मकान मालिकों पर दबाव डालकर उनकी संपत्ति कब्जाई गई। सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण खड़े किए गए और सालों तक प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। हालांकि हाल ही में सरकार के आदेश पर प्रशासन ने इन संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया है। कई कब्जाई गई संपत्तियों को मुक्त कराया गया है, जिनकी कुल कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये आँकी जा रही है।

मोहन सरकार का सख्त रुख

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सत्ता संभालते ही साफ किया था कि उनकी सरकार अपराध और माफियाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यही वजह है कि इस कार्रवाई को उनकी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि अगर राजधानी में ही माफियाओं को संरक्षण दिया जाता रहेगा तो यह संदेश पूरे प्रदेश में गलत जाएगा। इसलिए मछली परिवार पर हुई कार्रवाई को उदाहरण बनाने की कोशिश की जा रही है।

क्या और नाम आएंगे सामने?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल सारिक मछली ही असली अपराधी है या उसके पीछे और भी बड़े नाम छुपे हैं? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मछली परिवार का संरक्षण केवल एक नेता तक सीमित नहीं था, बल्कि कई रसूखदार लोग इस जाल का हिस्सा रहे हैं। क्या प्रशासन अब उन नेताओं और अधिकारियों का भी नाम उजागर करेगा, जिन्होंने मछली परिवार की मदद की? क्या केवल संपत्ति जब्ती से माफिया नेटवर्क टूट जाएगा, या इसके पीछे की राजनीतिक साजिश भी उजागर होगी? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं।

विपक्ष का मोहन सरकार पर करारा हमला

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सारिक मछली प्रकरण को भाजपा सरकार की दोहरी राजनीति करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा बाहर से "ड्रग्स मुक्त मध्यप्रदेश" का नारा देती है, लेकिन भीतर ही भीतर माफियाओं को नेता बनाकर सत्ता की राजनीति करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जिन नेताओं ने मछली परिवार को संरक्षण दिया, उन्हें भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। दूसरी ओर, भाजपा ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि पार्टी किसी भी अपराधी को बख्शने के पक्ष में नहीं है। पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि यदि सारिक मछली ने अपराध किया है, तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। भाजपा ने यह भी दावा किया कि यही फर्क है उनकी सरकार और विपक्ष की सरकारों में जहाँ अपराधियों को संरक्षण नहीं बल्कि सजा मिलती है।

भोपाल में नशे का बढ़ता कारोबार चिंता का सबब

इस कार्रवाई ने राजधानी भोपाल के नागरिकों को झकझोर दिया है। लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि जब एक बड़ा माफिया भाजपा का पदाधिकारी बन सकता है, तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? युवाओं में यह भी चर्चा है कि राजनीतिक रसूख के दम पर ड्रग्स माफिया ने कितने परिवारों को बर्बाद किया और अब जाकर उस पर कार्रवाई क्यों हुई। शारिक मछली प्रकरण केवल एक अपराधी पर कार्रवाई का मामला नहीं है, बल्कि यह राजनीति और अपराध के गठजोड़ की गहरी कहानी कहता है। यह साफ है कि जब तक ऐसे माफियाओं को नेताओं और सत्ता का संरक्षण मिलता रहेगा, तब तक प्रदेश को ड्रग्स मुक्त और अपराध मुक्त बनाना मुश्किल होगा। मोहन सरकार की इस कार्रवाई ने जरूर संदेश दिया है कि अपराधियों पर लगाम कसने की मंशा गंभीर है। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब इस संरक्षण तंत्र का असली चेहरा उजागर किया जाएगा और उन नेताओं के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिन्होंने मछली परिवार जैसे माफियाओं को वर्षों तक बचाए रखा।

जनता अब यही देखना चाहती है कि सरकार केवल दिखावटी कार्रवाई तक सीमित रहती है या फिर राजनीतिक रसूखदारों का भी पर्दाफाश करती है। क्योंकि असली सवाल यही है। क्या मध्यप्रदेश सच में माफिया मुक्त होगा या फिर राजनीति और अपराध का यह पुराना गठजोड़ नए नामों के साथ चलता रहेगा?

सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करते, बल्कि संगठन और जनता के बीच मजबूत सेतु का काम करते हैं कैलाश विजयवर्गीय

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में भाजपा ने पिछले तीन दशकों में जिस मजबूती से अपनी पकड़ बनाई है, उसके पीछे कई बड़े नेताओं का योगदान रहा है। इन नेताओं में यदि सबसे प्रभावशाली और दूरदर्शी चेहरों की सूची बनाई जाए तो उसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का नाम प्रमुखता से दर्ज किया जाएगा। चाहे प्रदेश की राजनीति हो, संगठन को मजबूत करना हो या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की छवि को धार देना- हर मोर्चे पर विजयवर्गीय ने अपनी अलग पहचान बनाई है। आज जब मध्यप्रदेश की राजनीति का विश्लेषण किया जाता है, तो यह साफ दिखता है कि भाजपा का जनाधार लगातार स्थिर और मजबूत बना है। इसमें मुख्यमंत्री, सांसद और अन्य नेताओं का योगदान तो है ही, लेकिन मालवा सहित अन्य क्षेत्रों में भाजपा की गहरी पैठ और संगठनात्मक मजबूती का श्रेय काफी हद तक कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व को जाता है।

उन्होंने इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और रतलाम जैसे जिलों ने प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विजयवर्गीय की राजनीति की शुरुआत भी इसी क्षेत्र से हुई। इंदौर नगर निगम से लेकर विधायक और मंत्री पद तक की उनकी यात्रा ने उन्हें आम कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। उनकी पहचान सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि संगठन को जोड़ने वाले सूत्रधार के रूप में है। यही कारण है कि मालवा में भाजपा का वोट बैंक लगातार बढ़ता गया।

संगठनात्मक कौशल और भाजपा की मजबूती

कैलाश विजयवर्गीय की असली ताकत उनका संगठनात्मक कौशल है। वे सिर्फ भाषण देने या चुनावी रणनीति बनाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच लगातार संवाद स्थापित करते हैं। यही कारण है कि भाजपा के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में उनके प्रति विशेष लगाव देखने को मिलता है। विजयवर्गीय ने कई बार साबित किया है कि वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संगठन को एकजुट रख सकते हैं। प्रदेश में गुटबाजी की राजनीति का असर भाजपा पर भी पड़ता रहा है, लेकिन विजयवर्गीय ने अपने व्यवहार और नेतृत्व क्षमता से कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखा। यही वजह है कि आज भी उन्हें भाजपा का संकटमोचक कहा जाता है।

प्रदेश से बाहर भी बढ़ा कद

विजयवर्गीय का कद सिर्फ मध्यप्रदेश तक सीमित नहीं रहा। भाजपा नेतृत्व ने उनके अनुभव और रणनीतिक समझ का उपयोग अन्य राज्यों में भी किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। वर्ष 2021 के चुनाव में जब भाजपा ने ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध लगाने का निर्णय लिया, तो पार्टी ने विजयवर्गीय को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने बंगाल में महीनों तक डेरा डाला, बूथ-स्तर तक संगठन खड़ा किया और कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया। यद्यपि भाजपा उस चुनाव में पूर्ण सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन पार्टी ने इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। भाजपा 3 से सीधे 77 सीटों पर पहुँची। यह उपलब्धि दिखाती है कि विजयवर्गीय की रणनीति ने बंगाल की राजनीति में भी नई करवट पैदा की।

राष्ट्रीय नेतृत्व में भरोसेमंद चेहरा

भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा उन नेताओं पर भरोसा जताता है जो कठिन परिस्थितियों में भी संगठन को मजबूती से खड़ा कर सकें। कैलाश जी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की टीम में विजयवर्गीय को एक भरोसेमंद रणनीतिकार माना जाता है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर चुनावी प्रबंधन तक, विजयवर्गीय का योगदान लगातार बढ़ रहा है। उन्हें प्रदेश से बाहर भी कई चुनावों में स्टार प्रचारक और समन्वयक की भूमिका दी जाती है।

भाजपा को एकजुट रखने की क्षमता

मध्यप्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती है गुटबाजी। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों दलों में गुटबाजी का असर समय-समय पर देखने को मिलता रहा है। ऐसे में विजयवर्गीय का कद इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वे संगठन को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखते हैं। उनका राजनीतिक व्यवहार समन्वयकारी है। वे न तो अत्यधिक आक्रामक हैं और न ही पूरी तरह से समझौता करने वाले। यही संतुलन उन्हें कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित करता है।

आगे की राजनीति में संभावनाएँ

मध्यप्रदेश में भाजपा की राजनीति आने वाले वर्षों में कई चुनौतियों और अवसरों से गुजरने वाली है। विजयवर्गीय की संगठनात्मक क्षमता, जनता से जुड़ाव और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता उन्हें भविष्य की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बनाती है। यदि भाजपा मध्यप्रदेश में सत्ता का नेतृत्व परिवर्तन करती है, तो विजयवर्गीय एक स्वाभाविक दावेदार के रूप में उभर सकते हैं। आज जब भाजपा मध्यप्रदेश में मजबूत स्थिति में है और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपना दायरा बढ़ा रही है तो विजयवर्गीय जैसे नेताओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। उनकी कार्यशैली, जनता से जुड़ाव और रणनीतिक दृष्टि उन्हें उन नेताओं की श्रेणी में खड़ा करती है जो न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य की राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

पर्यावरण प्रेमी भी हैं कैलाश जी

कैलाश विजयवर्गीय केवल राजनीति के ही योद्धा नहीं हैं बल्कि वे पर्यावरण के सच्चे प्रेमी भी हैं। राजनीति के हर दौर में उन्होंने पर्यावरण के प्रति अपनी इच्छाओं को आत्मसात किया है। इंदौर में लगातार पौधारोपण का अभियान चला रहे विजयवर्गीय द्वारा अब तक लगाए गए पौधों को 100 फीसदी जीवित रखने का भी रिकॉर्ड बनाया है। उनके नेतृत्व में शहर के रेवती रेंज की पहाड़ी पर 12,40,000 पौधे शहरवासियों ने लगाए थे, जो अब तक पहाड़ी पर लहलहा रहे हैं। इंदौर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने की दिशा में कैलाश विजयवर्गीय ने वृक्षारोपण अभियान चला रखा है। इस क्रम में वे शहर में पितृ पर्वत विकसित कर चुके हैं। जहां शहरवासियों के पितरों की याद में लाखों पौधे लगाए गए हैं।

भूपेश बघेल पर बढ़ा संकटः बेटे की गिरफ्तारी के बाद मानसिक संतुलन खोने के संकेत, खुद कर बैठे खुलासा

(पेज 1 का शेष)

क्योंकि देखा जा रहा है कि कुछ नेता बयानों के माध्यम से चैतन्य बघेल के पक्ष में बोल रहे हैं। इससे कांग्रेस की ही फजीहत होने वाली है। जबकि प्रदेश के कई समर्पित नेता हैं जो पार्टी को नई दिशा दे सकते हैं उनके विषय में बोलना चाहिए। चेतन्य बघेल के पक्ष में बोलकर तो ये नेता कांग्रेस की ही फजीहत कर रहे हैं।

मानसिक असंतुलन और विचित्र बयानों की झलक

चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल की मानसिक स्थिति को लेकर कई चर्चाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से दिए गए बयान ने सबको चौंका दिया, जब उन्होंने खुद स्वीकार किया कि राज्य में कभी अजीत जोगी की सरकार को गिराने में उनके और उनके परिवार की भूमिका थी। यह बयान न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से विस्फोटक था, बल्कि इससे यह संकेत भी मिले कि बघेल फिलहाल अत्यधिक मानसिक दबाव में हैं।

सत्ता के पीछे की पुरानी कहानी

पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान पुराने राजनीतिक घावों को फिर से कुरेद गया है। 2000 के दशक की शुरुआत में जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, तब सत्ता परिवर्तन की जो घटनाएं हुई, वे अब फिर चर्चा में हैं। भूपेश बघेल द्वारा खुद ही अपने हाथ होने की बात सार्वजनिक रूप से कह देना यह बताता है कि या तो वह जानबूझकर अपनी पार्टी को संदेश दे रहे हैं या फिर उनके मानसिक संतुलन पर संकट गहराता जा रहा है।

अंधविश्वास की गिरफ्त में भूपेश?

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बघेल अब तंत्र-मंत्र, जादू-टोना और श्राप जैसे अंधविश्वासों की ओर झुक गए हैं। उनके करीबी सूत्रों के अनुसार, वह कुछ दिनों से धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ-हवन और विशेष तांत्रिक कर्मकांडों में लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव उनके बढ़ते मानसिक दबाव और असहजता का संकेत है।

ईडी की जांच और चेतन्य के खुलासे

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही पूछताछ में चैतन्य बघेल ने जिन तथ्यों को उजागर किया है, वे भूपेश बघेल और उनके करीबियों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। जांच एजेंसी को ऐसे कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जो वित्तीय गड़बड़ियों और सत्ता के दुरुपयोग की ओर संकेत करते हैं। सूत्रों के अनुसार चैतन्य ने कुछ ऐसे नाम भी बताए हैं, जिन्हें 'चंडाल चौकड़ी' कहा जा रहा है। यह चौकड़ी सरकार के दौरान निर्णय लेने की आड़ में कथित रूप से करोड़ों के खेल में शामिल रही थी।

कांग्रेस के लिए बढ़ी मुश्किल

भूपेश बघेल के हालिया बयानों और परिवार से जुड़ी घटनाओं के चलते कांग्रेस पार्टी असहज स्थिति में आ गई है। केंद्र में भाजपा सरकार और राज्य में बदलते सियासी समीकरणों के बीच अब कांग्रेस नेतृत्व के लिए बघेल को लेकर स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक होता जा रहा है। जहां कुछ नेता चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं कुछ बघेल से दूरी बनाते दिख रहे हैं।

कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

जांच एजेंसियों के रुख और चैतन्य की स्वीकारोक्तियों को देखते हुए यह आशंका गहराती जा रही है कि भूपेश बघेल को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह न केवल छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है, बल्कि कांग्रेस की छवि को भी गहरा आघात पहुंचा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री की छवि एक समय किसान पुत्र और जननेता की थी, लेकिन हालिया घटनाओं ने उनकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित किया है। जनता के बीच अब यह चर्चा आम है कि क्या वाकई सत्ता में रहते हुए उनके कार्यकाल में पारदर्शिता थी? क्या जो बातें वे आज कह रहे हैं, वे पहले क्यों नहीं कहीं? भूपेश बघेल इस समय जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पुत्र की गिरफ्तारी, ईडी की जांच, पार्टी के भीतर बढ़ती दूरी और मानसिक असंतुलन जैसे संकेत उनकी स्थिति को राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से जटिल बना रहे हैं।

सम्पादकीय

बिहार की राजनीति में आखिर मतदाता पर्ची क्यों बनी चर्चा का विषय ?

लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान की प्रक्रिया लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है। यह केवल नागरिक अधिकार नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है। मतदाता पर्ची यानी वोटर स्लिप इसी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है, जो मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुँचने और अपने मताधिकार का उपयोग करने में सहायता करती है। लेकिन हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में यह छोटी-सी दिखने वाली पर्ची बड़े विमर्श का विषय बन गई है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्यों बिहार के राजनीतिक हलकों में मतदाता पर्ची इतनी चर्चा में है? इसके पीछे कई कारण हैं- जनता का भरोसा, पारदर्शिता का सवाल, तकनीकी बदलाव और राजनीतिक रणनीति। मतदाता पर्ची चुनाव आयोग की ओर से जारी वह दस्तावेज है, जिसमें मतदाता का नाम, पता और मतदान केंद्र की जानकारी होती है। यह मतदान के दिन मतदाता की पहचान की सुविधा देती है। हालांकि पहचान के लिए आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेज भी मान्य हैं, लेकिन मतदाता पर्ची सबसे आसान और सीधी पहचान का साधन है। बिहार जैसे बड़े और ग्रामीण बहुल राज्य में मतदाता पर्ची की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गाँव-गाँव तक फैले मतदान केंद्रों पर मतदाता को यह पर्ची बताती है कि किस बूथ पर जाकर उन्हें मतदान करना है। हाल के वर्षों में बिहार की राजनीति में मतदाता पर्ची को लेकर कई तरह की बहसें शुरू हुई हैं।

बिहार में कई बार यह आरोप लगता रहा है कि पर्चियों का दुरुपयोग कर फर्जी मतदान कराया जाता है। पर्चियों का बंटवारा जिस पारदर्शिता से होना चाहिए, वह हमेशा नहीं होता। कई बार विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि पर्चियाँ सही ढंग से वितरित नहीं की गई, जिससे वोटरों को दिक्कत होती है। कुछ दलों का मानना है कि मतदाता पर्ची के वितरण की प्रक्रिया राजनीतिक रूप से प्रभावित होती है। यदि मतदाता समय पर पर्ची से वंचित रह जाए, तो उसका मतदान प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि विपक्ष बार-बार मांग करता है कि चुनाव आयोग इसकी निगरानी को और मजबूत करे।

आज जब वोटर हेल्पलाइन ऐप, एसएमएस और वेबसाइट के जरिए मतदाता अपनी जानकारी पा सकता है, तब सवाल उठता है कि क्या मतदाता पर्ची की जरूरत है? कुछ नेताओं का तर्क है कि डिजिटल व्यवस्था से सबकुछ पारदर्शी हो सकता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की सीमित पहुँच इसे अव्यावहारिक बनाती है।

चुनावी मैदान में मतदाता पर्ची केवल पहचान पत्र नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए 'मतदाता तक पहुँचने का माध्यम' भी है। दलों के कार्यकर्ता पर्चियाँ बांटने के साथ मतदाता को अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि पर्ची बंटवारे की प्रक्रिया पर दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी चलता है। बिहार में मतदाता पर्ची को लेकर चर्चा इसलिए भी गहरी है क्योंकि यहाँ का चुनावी माहौल हमेशा गर्म और संवेदनशील रहा है। बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, जहाँ डिजिटल माध्यमों की पहुँच सीमित है।अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण मतदाता पर्ची की अनुपस्थिति कई बार लोगों को मतदान से वंचित कर देती है। चुनाव आयोग समय-समय पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि मतदाता पर्ची सभी तक पहुंचे। बूथ स्तर पर कर्मचारी घर-घर जाकर पर्चियाँ बांटते हैं। लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं—कभी कर्मचारी की लापरवाही, कभी राजनीतिक दबाव, तो कभी मतदाता की अनुपस्थिति, इन सब वजहों से गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। आयोग ने हाल ही में यह भी स्पष्ट किया है कि पर्ची न होने पर भी मान्य पहचान पत्र दिखाकर मतदान किया जा सकता है। बावजूद इसके, आम मतदाता में भ्रम बना रहता है। बिहार की राजनीति में मतदाता पर्ची का चर्चा में आना इस बात का प्रतीक है कि यहाँ लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी और संवेदनशील हैं। यह मुद्दा सिर्फ एक पर्ची का नहीं, बल्कि मताधिकार के इस्तेमाल, पारदर्शिता और भरोसे का है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर मतदाता को उसकी सुविधा और अधिकार समान रूप से मिले। इसलिए यह जरूरी है कि मतदाता पर्ची केवल एक कागज न रहकर, लोकतंत्र की बुनियादी ताकत को मजबूत करने का साधन बने।

सियासी गहमागहमी

कौन बनेगा मध्यप्रदेश का नया मुख्य सचिव?

मध्यप्रदेश की नौकरशाही में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है "आखिर नया मुख्य सचिव कौन बनेगा?" यह सवाल अब उतना ही चर्चित हो चला है जितना चुनाव के वक्त "मुख्यमंत्री कौन?" होता है। अनुराग जैन को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर किसी और के सिर पर मुख्य सचिव की टोपी सजाई जाएगी। इस पर अटकलों का बाजार गर्म है। सरकारी गलियारों में तो माहौल ऐसा है मानो कोई आईपीएल ऑक्शन चल रहा हो। उम्मीदवार लाइन में खड़े हैं और सबको उम्मीद है कि शायद अगली गेंद उनकी झोली में आ गिरे। कोई वरिष्ठता का हवाला दे रहा है, कोई अनुभव का झंडा लहरा रहा है, और कोई तो सीधा सत्ता के गलियारे में अपने "कनेक्शन" की चाय पी रहा है। जहाँ आम जनता सोचती है कि मुख्य सचिव बदले या रहे, उनके बिजली के बिल और गड्ढेदार सड़कों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वहीं नेताओं और अफसरों की धड़कनें तेज हैं। आखिर ये कुर्सी वही है, जिस पर बैठकर फैसलों के पन्ने पलटे जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मध्यप्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलेगा या "एक्सटेंशन की सरकार" कायम रहेगी। फिलहाल तो मामला वही पुराना है "कुर्सी बड़ी है, दावेदार और भी बड़े हैं।"

नीतीश का यू-टर्न भाजपा के लिए बना है चिंता कारण

भारतीय राजनीति में अगर कोई नेता सबसे ज्यादा "यू-टर्न" लेने का पेटेंट करा सकता है, तो वह हैं हमारे नीतीश बाबू। दिन में भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, तो रात में महागठबंधन के सपनों में खो जाते हैं। अब सवाल यही है कि चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार फिर से मोदी और भाजपा पर दबाव बनाएंगे? भाजपा के नेता भले ही मंच से "डबल इंजन सरकार" का गुणगान करें, लेकिन मन ही मन उन्हें यही डर सताता है कि कहीं "तीसरा इंजन" न निकल आए। नीतीश बाबू की राजनीति इतनी लचीली है कि इसे देखकर रबर भी शर्मा जाए। वे कभी लालू के गले मिलते हैं, कभी मोदी का हाथ थाम लेते हैं, और कभी अकेले ही "सुशासन" की नौका पर निकल पड़ते हैं। दरअसल, भाजपा के लिए यह चिंता का विषय है कि नीतीश बाबू दोस्ती निभाने से ज्यादा "कुर्सी टिकाने" में विश्वास रखते हैं। जिस कुर्सी पर वे बैठे हों, उसे छोड़ना उन्हें नागवार गुजरता है, चाहे इसके लिए कितनी भी बार गठबंधन बदलना पड़े। चुनाव बाद की राजनीति का असली रोमांच यह नहीं होगा कि किसे बहुमत मिलेगा, बल्कि यह होगा कि नितीश बाबू किसके साथ बैठकर चाय पिएंगे।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, मगर दिन-रात धूप-पानी मे मेहनत करने वाले किसान-मजदूर मुनाफे का 1% भी नहीं कमाते हैं। आज, इन किसानो से उनके खेतो मे मिलकर उनकी आपबीती जानी।
बड़े शहरो मे 1000-2000 रुपए किलो बिकता है, मगर इन मेहनतकशो, पूरे उद्योग की नीव को, नाम मात्र का दाम मिलता है।
-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

जबलपुर मे आज सबसे बड़े फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ है, याद होगा कि इस फ्लाईओवर के निर्माण की प्रकिया तब शुरू हुई थी, जब मै मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। मै केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी @nitin_gadkari को भी बधाई देता हूँ कि उन्होने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि कांग्रेस की सरकार के समय मे मैने इस फ्लाइओवर के लिए प्रस्ताव भेजा था।**-कमलनाथ**
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

व्यापक निवेश अवसर

सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना

योजना के प्रमुख उद्देश्य

- मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी को कम मूल्य पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराना
- ट्रांसमिशन हानि कम करना एवं सीधे खपत स्थल पर बिजली पहुंचाना
- 33/11 केवी उपकेंद्रों पर ओवरलोडिंग, लो-वोल्टेज और पावर कट की समस्या कम करना
- किसान को सिंचाई के लिये दिन में बिजली उपलब्ध कराना

नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार

- सब-स्टेशन की 100% क्षमता तक की परियोजनाओं की स्थापना
- परियोजनाओं को पीएम कुसुम-सी योजनांतर्गत उपलब्ध केंद्रीय अनुदान का लाभ लेने का विकल्प
- 1900 से अधिक विद्युत सबस्टेशन एवं 14500 मेगावॉट क्षमता सौर परियोजनाओं के चयन हेतु उपलब्ध
- पीएम कुसुम योजना में 3.45 लाख पम्प का लक्ष्य
- वोकल फॉर लोकल - स्थानीय उद्यमियों के लिए निवेश एवं रोज़गार सृजन का उचित अवसर
- वित्त पोषण की सुगमता के लिए बैंकों से समन्वय
- परियोजनाओं में AIF के तहत 7 वर्षों तक 3% ब्याज में छूट
- Reactive Power प्रबंधन से अतिरिक्त आय

R.O. No. : D19143/25

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

किसानों के लिये जरूरी है कमलनाथ का कर्ज माफी मॉडल

पीयूष बबेले
(चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार)

मध्य प्रदेश आज भी एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां करीब 70 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है। इसके बावजूद प्रदेश में किसानों की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सत्ताधारी भाजपा ने किसानों से जो भी वादे किये वे निभाए नहीं। न तो वादे के मुताबिक 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हुई और न ही 2023 के विधानसभा चुनाव में गेहूं और धान का वह न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया, जिसका वादा भाजपा ने किया था। जबकि इस दौरान कृषि लागत लगातार बढ़ती गई है। ऐसे में जरूरी है कि पलटकर देखा जाए कि प्रदेश के किसानों के हित के लिए अतीत में कौन से बढिया काम हुए थे और क्या उन्हें दुहराया जा सकता है। पाठकों को याद होगा कि दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ ने सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी के आदेश पर दस्तखत किये थे। कर्ज में फंसे किसानों का पूरा अध्ययन करने के बाद कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 में किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना थी। कमलनाथ सरकार ने दो चरणों में करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, जो प्रदेश के लिये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

इस योजना के पहले चरण में 20 लाख 23 हजार 136 किसानों का कर्ज माफ किया था और दूसरे चरण में 6 लाख 72 हजार 245 किसानों का कर्ज माफ किया गया। इस तरह करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया। कमलनाथ अगले चरण में और भी किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी सरकार गिरा दी गई।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि कमलनाथ ने किसानों का कर्ज तो माफ किया लेकिन राजकोष पर इसका ज्यादा बोझ नहीं पड़ने दिया। कर्जमाफी के पहले चरण में 7108.96 करोड़ रुपये और दूसरे चरण में 4538.03 करोड़ रुपये यानी कुल मिलाकर 11,646.96 करोड़ रुपये के किसान कर्ज माफ किये गए। देवास, खरगौन, मंदसौर, सीहोर और विदिशा जिलों में तो एक-एक लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया गया। छिंदवाड़ा में करीब 75 हजार किसानों का कर्ज माफ किया गया। मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिये यह काफी बड़ी संख्या है और खासकर कमलनाथ सरकार को जिस तरह का खाली खजाना मिला था, उसमें तो यह और बड़ी चुनौती थी।

लेकिन इस चुनौती से निपटने में कमलनाथ का अनुभव काम आया था। छिंदवाड़ा से 40 साल तक सांसद रहने के कारण वे किसानों की जरूरतों को बखूबी जानते थे, तो दूसरी तरफ देश के वाणिज्य मंत्री के रूप में उनका अनुभव बैंकों पर नकेल कसने में काम आया। कमलनाथ ने बैंकों से कहा कि वे उसी तरह किसानों का कर्ज माफ करें जिस तरह वे कॉरपोरेट का कर्ज माफ करते हैं। इसका मतलब यह था कि संपूर्ण बकाया राशि की जगह बैंक एक ऐसी राशि पर समझौता करें तो बैंक और राज्य सरकार दोनों को मंजूर हो। कमलनाथ के बैंकिंग, मौद्रिक नीति और अर्थशास्त्र के बारीक ज्ञान के सामने बैंकों की दलीलें नहीं टिकीं और 11,646.96 करोड़ का कर्ज किसानों के सिर से उतर गया।

अब जरा आज की तस्वीर पर गौर करें। आज स्थिति यह कि किसान पिछले एक महीने से यूरिया न मिल पाने के कारण प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। नकली खाद और बीज किसानों के लिये दूसरा बड़ा संकट हैं। तीसरी समस्या यह आ गई है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर किसानों से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार और किसानों ने मिलकर खरीब 2024 में करीब 1792 करोड़ रुपये फसल बीमा का प्रीमियम दिया। उसके बाद राज्य सरकार के अधिकारियों ने माना कि सोयाबीन की फसल को 50 से 70 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। लेकिन बीमा कंपनी ने सैटेलाइट सर्वे का बहाना बनाकर इसे खारिज कर दिया और किसानों को बीमा क्लेम के नाम पर 100-200 रुपये पकड़ा दिये।

2020 में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद से किसानों के साथ लगातार यही हो रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिये मौजूदा सरकार सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी करे और इसके लिये कमलनाथ मॉडल को अपनाए। इसी तरह बीमा कंपनियों पर भी कमलनाथ के अनुभव का लाभ लेते हुए लगाम कसे।

सरकार को यह समझना होगा कि जब किसान का कर्ज माफ किया जाएगा तो किसान के पास कुछ पैसा बचेगा। इसी पैसे को किसान बाजार में खर्च करेगा और इससे आर्थिक गतिविधि का पहिया घूमेगा। आर्थिक गतिविधि के लिये पूंजी का गतिमान होना बहुत जरूरी है। अगर एक 10 का नोट एक व्यक्ति की जेब में है तो वह सिर्फ 10 रुपये हैं। लेकिन अगर किसान ने 10 रुपये ऑटो वाले को दिये, ऑटो वाले ने परचून वाले को दिये, परचून वाले बच्चे की स्कूल फीस में दिये, स्कूल वालों ने ऐसे स्टेशनरी वाले को दिये और स्टेशनरी वाले किसान से गेहूं खरीदा तो पांच हाथों से गुजरकर यह 10 रुपये 50 रुपये की आर्थिक गतिविधि कर देते हैं। इसी को वेलोसिटी ऑफ रुपी कहते हैं।

इसलिये बेहतर होगा कि मध्य प्रदेश सरकार हर महीने 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के बजाय किसानों का कर्ज माफ करे और किसानों की जेब में पैसा पहुंचाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेज करे। मुझे लगता है कि सरकार अगर इस संबंध में कमलनाथ जी से कोई सलाह मांगेगी तो वे प्रदेश हित में जरूर सलाह देंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कैंसर हॉस्पिटल का उन्नयन

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएँ नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हैं। इसी क्रम में डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित कैंसर अस्पताल की जी प्लस टू (ग्राउंड फ्लोर प्लस दो मंजिल) बिल्डिंग का विस्तार होकर जी प्लस सिक्स (ग्राउंड फ्लोर प्लस छः मंजिल) में उन्नयन होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने बताया कि इन परियोजना के लिए लगभग 39.36 करोड़ रूपए की पुनरीक्षित राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कार्य को जल्द गति दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार यह बिल्डिंग सिर्फ किसी भवन या निर्माण कार्य का विस्तार नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के लिए उम्मीद की नई किरण है। कैंसर अस्पताल के जी प्लस सिक्स के विस्तार के साथ राज्य की जनता को भी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि यह कदम छत्तीसगढ़ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई पहचान दिलाने की दिशा में अग्रसर होगा।

कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन, नकुलनाथ के लिए जुटा लिए डेढ़ दर्जन विधायक और पूर्व मंत्री

-समता पाठक

जगत प्रवाह. छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में बीजेपी की राज्य सरकार को जमकर ललकारा गया। यहां खाद की किल्लत सहित किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने दो दिन पूर्व इस आंदोलन का ऐलान किया था। बेटे के इस आव्हान पर पिता कमलनाथ सक्रिय हुए और जबर्दस्त शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी के करीब डेढ़ विधायकों व पूर्व मंत्रियों को यहां बुला लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी छिंदवाड़ा पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कलेक्टर नहीं मिले तो प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ते के गले में ज्ञापन लटका दिया।

कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टरों में बैठकर प्रदेशभर से आए किसान और कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता सभा स्थल जेल बगीचे पहुंचे। यहां वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की सभा हुई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है लेकिन बीजेपी और सरकार यह बात नहीं मान रही है। किसान कतार में लगे हैं और पुलिस उनको लाठियां मार रही है। जीतू पटवारी ने यहां - 'खाद चोरों, कुर्सी छोड़ो' का नया नारा दिया। पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा कि किसान यूरिया के लिए लाइन में लगा लेकिन सरकार ने उनपर FIR कर दी। कितने लोगों पर FIR करोगे, कितनों को गिरफ्तार करोगे? हम सब गिरफ्तार होने को तैयार हैं।

डेढ़ दर्जन विधायकों, पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं को जुटाया

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया और ओमकार सिंह मरकाम ने भी सभा को संबोधित किया। सभा और रैली में करीब 10 हजार किसानों, कांग्रेसियों के जुटने का दावा किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में इसे कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने गढ़ में पार्टी के करीब डेढ़ दर्जन विधायकों, पूर्व मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं को जुटा लिया। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके तो बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ यहां आए। मंच पर कांग्रेस के करीब 80 नेता बैठे थे।

गणेश चतुर्थी

सिर्फ एक पर्व नहीं, जीवन बदलने का उत्सव

आज की बात
प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

"गणपति बप्पा मोरया!" यह केवल एक जयकारा नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का आह्वान है जो हर साल भाद्रपद महीने में पूरे भारत को एक सूत्र में बाँध देता है। जब मिट्टी से बने गणपति घर-आंगन और पंडालों में विराजते हैं, तो वे अपने साथ उम्मीद, विश्वास और वह गहरा संदेश लाते हैं कि जीवन की हर बाधा उत्सव में बदली जा सकती है। भगवान श्रीगणेश का जन्मोत्सव केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक जीवंत अध्याय है। विघ्नहर्ता गणेश हमारे भीतर की कमजोरियों और बाहर की चुनौतियों को हराने के सबसे बड़े प्रेरणास्रोत हैं। वे बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के दाता माने जाते हैं, क्योंकि ये तीनों केवल सही मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होते हैं।

एकता और सामूहिकता का पर्व

गणेशोत्सव की सबसे बड़ी शक्ति इसकी सामूहिकता में छिपी है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जब इसे घरों से निकालकर सार्वजनिक पंडालों तक पहुँचाया, तो यह केवल अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना जगाने का साधन नहीं था, बल्कि समाज को यह सिखाने का प्रयास भी था कि जब हम एक साथ आते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी हो जाती है। आज यह पर्व धर्म से ऊपर उठकर एकता, संस्कृति और सामूहिक संकल्प का प्रतीक बन चुका है।

इंदौर की आस्थाः श्री खजराना गणेश जी

इंदौर की आस्था, भक्ति और एकता का प्रतीक हैं श्री खजराना गणेश जी, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों को आत्मिक शांति और असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं, बड़ा गणपति मंदिर अपनी भव्य प्रतिमा के साथ यह संदेश देता है कि विश्वास जितना विशाल होगा, उतनी ही बड़ी सफलताएँ जीवन में प्राप्त होंगी। इन्हीं प्रेरणाओं को चरम पर ले जाता है अनंत चतुर्दशी का जल समारोह, जब हजारों लोग संगठित होकर आस्था की धारा प्रवाहित करते हैं। यह अनूठा संगम हमें सिखाता है कि भक्ति, विश्वास और एकता से ही जीवन और समाज महान बनता है। जो समाज की एकता, उत्साह और सामूहिक शक्ति का जीवंत उदाहरण है।

आस्था के पाँच महान केंद्र : पूरे देश में भक्ति और एकता की लहर

1.लालबागचा राजा (मुंबई, महाराष्ट्र)
करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र। यहाँ माँगी गई हर मुराद पूरी होने की मान्यता है। अनंत चतुर्दशी की शोभायात्रा विश्वप्रसिद्ध है।

2.खैराताबाद गणेश (हैदराबाद, तेलंगाना)
40–60 फीट ऊँची विशालकाय प्रतिमा हर साल नया कीर्तिमान रचती है। यहाँ का माहौल किसी महाकुंभ से कम नहीं होता।

3.गौरीगंज गणेश उत्सव (लखनऊ, उत्तर प्रदेश)
अवध की तहज़ीब और लोक-संस्कृति से सराबोर, यहाँ की झाँकियाँ और शोभायात्राएँ पूरे क्षेत्र को एक परिवार की तरह जोड़ देती हैं।

4.कोलकाता गणेश उत्सव (पश्चिम बंगाल)
दुर्गापूजा की शैली में बने आर्टिस्टिक पंडाल और अनोखी प्रतिमाएँ कला और भक्ति का अद्भुत संगम पेश करती हैं।

5.बेंगलुरु गणेश उत्सव (कर्नाटक)
यह केवल पूजा नहीं, बल्कि संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजा उत्सव है, जहाँ बड़े कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देना सम्मान समझते हैं।

करियर और जीवन में बप्पा से लें यह पांच प्रेरणाएं

1.बड़ी आँखें– दूरदृष्टि और एकाग्रता
बड़ी आँखें सिखाती हैं कि हमें हर काम शुरू करने से पहले दूर तक देखने की आदत डालनी चाहिए। जीवन और प्रबंधन में दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति ही सही समय पर सही निर्णय ले सकता है।

2.बड़े कान– सुनने की कला
गणेश जी के विशाल कान बताते हैं कि अच्छा लीडर वही है जो सबकी सुनता है। आधुनिक जीवन में, सुनने से न केवल समस्याओं का समाधान निकलता है बल्कि टीम और परिवार में विश्वास भी मजबूत होता है।

3.बड़ा पेट– सहनशीलता और धैर्य
उनका विशाल पेट हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन की अच्छी-बुरी हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक पचाना चाहिए। आधुनिक मैनेजमेंट में धैर्य और टॉलरेंस ही टीम को संकट से निकालकर आगे बढ़ाते हैं।

4.टूटा दाँत– अपूर्णता में पूर्णता
टूटा हुआ दाँत सिखाता है कि जीवन में सफलता के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, अपूर्णता के साथ भी महान काम किए जा सकते हैं। यह मैनेजमेंट फंडा है कि कमियों के बावजूद अपनी ताकतों पर ध्यान दो, वही आपको आगे ले जाएगी।

5.मूषक वाहन– विनम्रता और नियंत्रण
चूहे जैसे छोटे वाहन पर बैठना दिखाता है कि बड़ा इंसान भी छोटे साधन से बड़ा काम कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे टेक्नोलॉजी हो या रिसोर्स, असली मैनेजमेंट उस पर नियंत्रण और संतुलन बनाने में है।

श्री गणेश चतुर्थी का उत्सव केवल पूजा और विसर्जन तक सीमित नहीं है। यह हमें अपने भीतर के गणपति को जगाने का अवसर देता है। इस बार जब आप बप्पा की आराधना करें, तो केवल मुरादें न माँगें, बल्कि यह संकल्प लें कि आप उनके गुणों को जीवन में उतारेंगे। आइए, इस गणेशोत्सव को केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि नई शुरुआत की तरह मनाएँ। अपने अंदर की कमजोरियों का विसर्जन करें और धैर्य, विवेक, साहस व विनम्रता को स्थापित करें। यही गणपति बप्पा की सच्ची आराधना है और इसी में जीवन व राष्ट्र की प्रगति का रहस्य छिपा है।

लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों की लचर कार्यशैली के चलते शिक्षा विभाग में आपातकाल की स्थिति

-बद्री प्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। दिया तले अंधेरा कैसे होता है इसका जीता जागता उदाहरण है नरसिंहपुर जिले का शिक्षा विभाग। मध्यप्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का यह गृह जिला है। जिले में महीनों से प्रमुख चारों पद रिक्त हैं और प्रभारी व्यवस्था से अव्यवहारिक रूप से निरीक्षण मॉनिटरिंग प्रशासनिक कार्य विभागीय निर्णय सब बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। यह स्थिति हो गई है कि प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यों में विभागीय अमले और आम जनता तक को दोनों मंत्रियों के बीच फंसे होने का बहाना और रोना रोकर अपनी चांदी काट रहे हैं और राजनीतिक और शासन स्तर को बेवजह ही बदनाम करने से भी नहीं चूक रहे हैं। पिछले दो-तीन सालों से आलम यह है कि विभागीय कर्मचारियों को बात-बात पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, एडीपीसी और ब्लॉकों में बैठे विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं विकासखंड स्त्रोत समन्वयक द्वारा सैकड़ों हजारों नोटिस जारी किए गए हैं और कार्यवाही के नाम पर नतीजा सफर है। पीछे के दरवाजे वाली सेटिंग के लिए नोटिस काट-काट कर जमकर उगाही का धंधा जिले में पिछले 2 साल से फल फूल रहा है और जिले के विभागीय मंत्री और उनके राजनीतिक नुमाइंदे तमाशाबीन बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष में नरसिंहपुर जिले में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, लेकिन अब हालात एकदम विपरीत दिशा में दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण है कि जिला शिक्षा विभाग के चारों मुख्य पद इस समय बिल्कुल रिक्त पड़े हुए है और एक पद जिसमें एक प्रभारी अधिकारी को छोड़कर बाकी में प्रभारी अधिकारी भी ढूढें से नही मिल रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी पद पर डाँगीढाना के प्राचार्य संदीप नेमा को प्रभारी बनाया गया है, अंदरुनी खबरों की माने तो इन्होंने भी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर प्रभार से मुक्त करने के लिए आवेदन दे दिया है।प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के संचालन निष्पादित करने वाला जिला शिक्षा केन्द्र का भी यही हाल है, जिला परियोजना समन्वयक आर पी चतुर्वेदी का पिछले माह सेवानिवृत्त हो गए हैं,जिसके बाद पद अब तक खाली है। नवागत एवं अन्य जिम्मेदारियों के लिए शिक्षक तैयार करने वाला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में भी प्राचार्य का पद खाली पड़ा हुआ है।

एक तरफ इस वर्ष का शिक्षण सत्र अभी शुरू ही हुआ है और जिला शिक्षा विभाग नरसिंहपुर का यह हाल है कि मुख्य पदों पर अधिकारी ही नही हैं। जिले में शीर्ष नेतृत्व न होने से शासन प्रशासन के द्वारा जारी आदेशों व निर्देशों का सही समय पर सही क्रियान्वयन न होने के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होने की सम्भावना है। आम जनता का भी यही कहना है कि शिक्षा मंत्री के गृह जिले में शिक्षा व्यवस्था लावारिस हालत में है तो सम्पूर्ण प्रदेश में क्या हालत हो सकती है इसका अंदाजा जिले से लगाया जा सकता है।

जिले में पूर्णकालिक अधिकारियों की नियुक्ति शासन स्तर से विभागीय अधिकारियों द्वारा की जावेगी स्थानीय स्तर पर प्रभारी नियुक्त जिला प्रशासन करेगा। मामले को उच्चाधिकारियों के पास बताया जाएगा

अरुण कुमार इंगले, जेडी शिक्षा, जबलपुर

मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी। देवरी विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण खरीफ फसलें पूर्णतः नष्ट हो गई हैं। नगरपालिका चौराहा पर एकत्रित होकर क्षेत्र के सैकडों किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम 12 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार देवरी को सौंपा हैं। इन्होंने मांग की है कि क्षेत्र में कृषकों को खाद उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाये। किसानों का कहना है कि क्षेत्र के कृषकों से साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा। अतिवृष्टि में क्षेत्र के अनेकों ग्रामों में गरीब परिवारों के नष्ट हुए आवासों को राहत राशि प्रदान करने, विद्युत विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर के नाम पर की जा लूट को रोकने, देवरी में मादक पदार्थों के विक्रय पर रोक लगाने सहित क्षेत्र की अनेक जनहित की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है।

फॉरेस्ट विभाग ने तेंदुआ पकड़ा

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। फारेस्ट विभाग के अधिकारियों ने आंदोलन की चेतावनी के पश्चात तेंदुआ को पकड़ा। केसला ब्लॉक के दुर्गेश धुर्वे ने बताया कि हाल में ही फारेस्ट अधिकारी की तैनाती होने के बावजूद एक बाघ मरा पाया गया। जल, जंगल, जमीन और जंगल का जानवर आदिवासियों के संरक्षण में सुरक्षित है। लेकिन जब से आदिवासियों का विस्थापन किया तब से शिकार बढ़ गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले कैसला के ग्रामों में एक तेंदुए का आतंक था जो रात के समय देखा गया। जिससे ग्रामीणों में ख़ौफ का माहौल था एवं ग्रामीणों ने तेंदुआ को पकड़ने की वन विभाग से भी गुहार लगाई थी। अब जब तेंदुआ पकड़ा गया हैं तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

CSPDCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

सस्ती नहीं मुफ्त बिजली की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

31 लाख परिवारों को मिल रहा हाफ बिजली बिल योजना का लाभ

15 लाख BPL परिवारों को **30 यूनिट फ्री + हाफ बिजली बिल योजना का लाभ**

डबल सब्सिडी केंद्र के साथ मिल रही राज्य की भी सब्सिडी

हर महीने **200-360 यूनिट** तक बिजली उत्पादन

बिजली बिल होगा **शून्य बची बिजली से होगी कमाई**

उपभोक्ता से बनें ऊर्जादाता

R.O. No. : 13388/ 1

पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना

मासिक बिजली बिल से भी कम ई.एम.आई. में लगाएं रूफ टॉप सोलर प्लांट

सौलर प्लांट क्षमता	केंद्र सरकार की सब्सिडी	राज्य सरकार की सब्सिडी	कुल सहायता राशि	आसान मासिक EMI
1 kW	₹30,000	₹15,000	₹45,000	₹167
2 kW	₹60,000	₹30,000	₹90,000	₹333
3 kW	₹78,000	₹30,000	₹1,08,000	₹800

*बैंक द्वारा 6% ब्याज दर पर आसान किश्तों में 10 वर्षों के लिए ऋण सुविधा (ई.एम.आई.) उपलब्ध

हमारा संकल्प
हाफ बिजली से मुफ्त बिजली

QR कोड स्कैन करें

आवेदन प्रक्रिया व अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं
https://pmsuryaghar.gov.in/

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)